International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 8.141
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 12 No. 6 July – August 2025

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऋणों और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मोनिष कुमार निर्मलकर[1], डॉ. एम माधुरी देवी[2], डॉ. सैयद सलीम अकील[3]

[1]*शोधार्थी, वाणिज्य संकाय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, (छ.ग.).*

[2]*शोध निर्देशक, (सहा. प्राध्यापक वाणिज्य), भिलाई महिला महाविधालय, भिलाई नगर, दुर्ग, (छ.ग.).*

[3]*सह शोध निर्देशक, (सहा. प्राध्यापक वाणिज्य), कल्याण स्नातकोत्तर महाविधालय, भिलाई नगर, दुर्ग, (छ.ग.).*

Corresponding Author - मोनिष कुमार निर्मलकर

DOI - 10.5281/zenodo.17286421

सार :

यह शोध एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक) के ऋण एवं अग्रिम, सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए का वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जो बैंक की वार्षिक रिपोर्टों, आरबीआई तथा नाबार्ड से संकलित किए गए हैं। इसमें ऋण वृद्धि, सकल एवं शुद्ध एनपीए की प्रवृत्ति तथा इनके मध्य सहसंबंध का परीक्षण किया गया है। परिणामस्वरूप यह स्पष्ट हुआ कि जहाँ ऋण एवं अग्रिम में निरंतर वृद्धि हुई है, वहीं सकल एवं शुद्ध एनपीए में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सहसंबंध विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि ऋण एवं अग्रिम और सकल एनपीए के बीच मध्यम ऋणात्मक संबंध है, जबकि ऋण एवं अग्रिम और शुद्ध एनपीए के बीच मजबूत ऋणात्मक संबंध पाया गया। यह दर्शाता है कि बैंक ने प्रभावी प्रावधान नीति और सुदृढ़ एनपीए प्रबंधन के माध्यम से न केवल अपनी परिसंपत्ति-गुणवत्ता को बेहतर बनाया है, बल्कि वित्तीय स्थिरता एवं ऋण वितरण क्षमता को भी सुदृढ़ किया है।

मुख्य शब्द : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऋण एवं अग्रिम, गैर निष्पादित संपत्ति, सकल एनपीए, शुद्ध एनपीए।

परिचय :

भारत की लगभग 65–70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, तथा कृषि को देश की अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ माना जाता है। हमारे देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण परिवेश में ही निवासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास तथा वहाँ के निवासियों की आर्थिक प्रगति में बैंकिंग संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। इसी संदर्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks – RRBs) की स्थापना की गई। इन बैंकों की स्थापना वर्ष 1975 में *क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976* के अंतर्गत संपादित की गई। इनका मूल उद्देश्य ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती तथा उपयुक्त बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही, कृषकों, श्रमिकों, कारीगरों, लघु उद्यमियों तथा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना भी इनकी प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

की पूँजी संरचना त्रिस्तरीय होती है। इसका अर्थ यह है कि इन बैंकों की पूँजी तीन संस्थानों में बाँटी जाती है—केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक। इनमें केंद्र सरकार की 50% हिस्सेदारी, राज्य सरकार की 15% हिस्सेदारी तथा प्रायोजक बैंक की 35% हिस्सेदारी होती है। (प्रायोजक बैंक वे राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं, जो ग्रामीण बैंकों को तकनीकी, प्रबंधन तथा प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएँ प्रदान करते हैं।)

1. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक :

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना 2 सितंबर 2013 को की गई भारत शासन, (वित्त मंत्रालय) द्वारा उपरोक्त अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया गया है। राज्य की स्थापना के समय नवगठित राज्य में 01 नवंबर 2000 को पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत थे। जिनमें से तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यथा बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर (स्थापित 20 अक्टूबर 1976), बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर (स्थापित 15 दिसंबर 1979) एवं रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायगढ़ (स्थापित 31 जनवरी 1981) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित थे। तथा सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंबिकापुर (स्थापित 24 अक्टूबर 1979) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तथा दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक, राजनांदगांव (स्थापित 12 मार्च 1980) देना बैंक द्वारा प्रायोजित थे।

दिनांक 02 सितंबर 2013 को पुनः अधिसूचना जारी की गयी जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा दुर्ग -राजनांदगांव ग्रामीण बैंक) का समामेलन करते हुए ***छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक*** का गठन किया गया तथा प्रधान कार्यालय, राजधानी रायपुर में रखा गया। इस प्रकार वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में केवल एक ग्रामीण बैंक कार्यरत है।

2. ऋण:

ऋण वह धनराशि है जो कोई व्यक्ति, संस्था या बैंक किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को एक निश्चित समयावधि के लिए इस शर्त पर प्रदान करता है कि उसे मूल धनराशि के साथ ब्याज चुकाना होगा।

भारत में ऋण (लोन) की शुरुआत और विकास :

1. प्राचीन और मध्यकालीन भारत: भारत में साहूकार, महाजन और बनिए मुख्य रूप से ऋण (कर्ज़) देते थे। यह ऋण प्रायः अनाज, धान या सोने-चाँदी के रूप में दिया जाता था। जिसका ब्याज (सूध/ब्याज) बहुत अधिक लिया जाता था, जिससे किसानों पर कर्ज़ का बोझ बढ़ जाता था।

2. औपनिवेशिक काल (ब्रिटिश शासन): ब्रिटिश काल में भारत में संगठित बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई। 1770 में 'हिन्दुस्तान बैंक' को भारत का पहला बैंक माना जाता है। इसके बाद बंगाल बैंक (1786), बॉम्बे बैंक (1840), मद्रास बैंक (1843) आदि स्थापित हुए। इन बैंकों ने व्यापारियों और ज़मींदारों को ऋण देना शुरू किया, लेकिन आम किसानों तक इनकी पहुँच नहीं थी। किसान अब भी साहूकारों पर निर्भर रहते थे।

3. स्वतंत्रता के बाद (1947 के पश्चात्): आज़ादी के बाद सरकार ने ग्रामीण और गरीब वर्ग तक बैंकिंग पहुँचाने पर ज़ोर दिया। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की स्थापना हुई, जिसने बड़े पैमाने पर

ऋण (लोन) उपलब्ध कराना शुरू किया। 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे किसानों, छोटे व्यापारियों और आम जनता को बैंक ऋण उपलब्ध होने लगे। इसके बाद शिक्षा ऋण, आवास ऋण, कृषि ऋण आदि योजनाएँ शुरू की गईं।

4. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऋण: 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) की स्थापना हुई, ताकि छोटे किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को आसानी से ऋण मिल सके और नाबार्ड (NABARD, 1982) ने कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रणाली को सुदृढ़ किया।

5. आधुनिक दौर (1991 के बाद): आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी बैंक (HDFC, ICICI, Axis आदि) सामने आए, जिन्होंने आवास ऋण, व्यक्तिगत ऋण और व्यवसायिक ऋण देना सरल बनाया। आज डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक कंपनियों ने ऋण लेने की प्रक्रिया को और तेज़ व सहज बना दिया है।

3. गैर-निष्पादित संपत्ति (एन पी ए):

आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में ऋण वितरण और उसकी समय पर वसूली वित्तीय स्थिरता की आधारशिला मानी जाती है। जब ऋण की भुगतान नियत समय पर नहीं हो पाती और उससे अपेक्षित आय (ब्याज अथवा मूलधन) प्राप्त नहीं होती, तब वह संपत्ति "गैर-निष्पादित संपत्ति" (Non-Performing Asset – NPA) की श्रेणी में आ जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, यदि किसी ऋण खाते में 90 दिनों से अधिक समय तक ब्याज अथवा किस्त का भुगतान न किया जाए, तो उसे गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार, सैद्धांतिक दृष्टि से एन पी ए वह परिसंपत्ति है जो बैंक की आय उत्पन्न करने की क्षमता को बाधित करती है और बैंकिंग प्रणाली की "आय सृजन क्षमता की विफलता" को दर्शाती है। ये न केवल किसी बैंक की वित्तीय स्थिति को कमजोर करती हैं, बल्कि समग्र अर्थव्यवस्था की प्रगति में भी बाधक बनती हैं। अतः एनपीए को वित्तीय स्वास्थ्य का प्रमुख संकेतक मानते हुए इसके प्रभावी प्रबंधन और नियंत्रण की आवश्यकता रहती है।

गैर-निष्पादित संपत्ति का वर्गीकरण:

RBI के मानकों के आधार पर एनपीए को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है -

- **उप-मानक परिसंपत्ति -** ऐसी एन पी ए जो 90 दिनों से अधिक और 12 माह से कम अवधि तक गैर-निष्पादित रही हो।
- **संदिग्ध परिसंपत्ति -** ऐसी एन पी ए 12 माह से अधिक समय तक बनी रही हो और जिसकी वसूली संदिग्ध हो।
- **हानि परिसंपत्ति -** ऐसी संपत्ति जिसे बैंक हानिप्रद मान लेते हैं, तथा जिसकी वसूली की संभावना बहुत कम होती है।

4. सकल एन पी ए:

सकल एनपीए वह कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति है, जिसका अर्थ है कि बैंक के पास ऐसे सभी ऋण या अग्रिम, जिनका ब्याज या मूलधन 90 दिनों या उससे अधिक समय तक बकाया रहता है और जिनसे बैंक को आय प्राप्त नहीं होती। सकल एनपीए में बिना किसी प्रावधान या कटौती के कुल बकाया राशि शामिल होती है। यह बैंक की

परिसंपत्तियों की गुणवत्ता का एक सामान्य संकेतक होता है। सकल एनपीए में उप-मानक परिसंपत्तियाँ, संदिग्ध परिसंपत्तियाँ और हानि परिसंपत्तियाँ सम्मिलित होती हैं।

5. शुद्ध एनपीए:

शुद्ध एनपीए बैंक के कुल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में से प्रावधानों को घटाकर बची हुई राशि को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि वास्तव में बैंक को अपने डूबे हुए कर्ज से कितना नुकसान हो सकता है।

शुद्ध एनपीए = सकल एनपीए – प्रावधान

साहित्य की समीक्षा:

सीएच श्रीनिवास, अकुला श्रीनिवास, (2018), के शोध पत्र के अनुसार, तेलंगाना ग्रामीण बैंक तेलंगाना राज्य के विकसित बैंकों में से एक है। तेलंगाना ग्रामीण बैंक ने पूरे ग्रामीण क्षेत्रो में अपनी शाखा नेटवर्क का विस्तार किया है। और एन.पी. ए के संबंध में जमा और अग्रिम पर इसका प्रदर्शन, एस.एच.जी को उधार, और सूक्ष्म-वित्तपोषण सभी अच्छे हैं और यह बैंक एक अच्छे विकास दर से बढ़ रहा है।

सुनीत सुरेश चंद्र कोपरा, (2017), के शोध पत्र के अनुसार, महाराष्ट्र के ग्रामीण जिलों में संचालित होने वाला महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक इस दो वर्ष की अवधि के दौरान विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक की तुलना में एनपीए का बेहतर प्रबंधन करता है। भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों में एनपीए की बढ़ती प्रवृत्ति न केवल बैंकों के लिए एक समस्या है, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चिंता है। यह प्रवृत्ति न केवल बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित करती है, बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी बाधित करती है।

डॉ. सोनिया नरूला और मोनिका सिंगला (2014), के शोध पत्र के अनुसार, ‘‘बैंक की गैर-निष्पादित संपत्तियों पर शोध अध्ययन’’ किया। उन्होंने पाया कि पंजाब नेशनल बैंक का सकल और शुद्ध एनपीए हर साल बढ़ रहा है, जिससे बैंक की तरलता प्रभावित हो रही है और नए ग्राहकों को ऋण देना कठिन हो गया है।

उद्देश्य :

1. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा प्रदान किए गए ऋणों और अग्रिमों का अध्ययन।
2. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के सकल एनपीए और शुद्ध एनपीए का अध्ययन।
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा सकल एनपीए के बीच सहसंबंध का अध्ययन।
4. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा शुद्ध एनपीए के बीच सहसंबंध का अध्ययन।

परिकल्पना :

H_{01} - छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा सकल एनपीए के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

H_{a1} - छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा सकल एनपीए के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध है।

H_{02} - छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा शुद्ध एनपीए के मध्य कोई संबंध नहीं है।।

H_{a2} - छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा शुद्ध एनपीए के मध्य महत्त्वपूर्ण संबंध है।

शोध कार्य विधि :

यह शोध कार्य पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। शोध कार्य के लिए आवश्यक आंकड़े शोध विषय से संबंधित विभिन्न अनुसंधानों, प्रतिष्ठित लेखों, पत्र एवं पत्रिकाओं, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की वार्षिक रिपोर्टों के माध्यम से संकलित किए गए हैं। शोध कार्य में तालिका, प्रतिशत, वार्षिक वृद्धि दर, माध्य, मानक विचलन, और सहसंबंध गुणांक एवं परिकल्पना परीक्षण के लिए टी टेस्ट का उपयोग जैसी सरल सांख्यिकीय विधियों का उपयोग किया गया है। इस शोध के लिए, बैंक की वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 तक की 10 वर्ष की वार्षिक रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है।

आकड़ों का विश्लेषण :

तालिका 6.1 – ऋण एवं अग्रिम, सकल एनपीए तथा शुद्ध एनपीए के वार्षिक वित्तीय आँकड़े। (राशि लाखों में,)

वर्ष	ऋण एवं अग्रिम	(%) परिवर्तन	सकल एन पी ए	सकल एन पी ए (%)	शुद्ध एन पी ए	(%) परिवर्तन
2015-2016	254651.14		22256.05	8.740%	20028.07	7.865%
2016-2017	264325.25	3.799%	30537.93	11.553%	19792.83	7.488%
2017-2018	283498.33	7.254%	44758.33	15.788%	25359.15	8.945%
2018-2019	304684.62	7.473%	41591.75	13.651%	19750.41	6.482%
2019-2020	351094.83	15.232%	19450.96	5.540%	7231.43	2.060%
2020-2021	445173.81	26.796%	13806.45	3.101%	3679.72	0.827%
2021-2022	521111.28	17.058%	13366.34	2.565%	0	0.000%
2022-2023	641627.69	23.127%	14564.79	2.270%	0	0.000%
2023-2024	803367.7	25.208%	16074.21	2.001%	0	0.000%
2024-2025	999439.64	24.406%	21440.43	2.145%	0	0.000%

तालिका में ऋण एवं अग्रिम, सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) तथा शुद्ध एनपीए में प्रतिशत परिवर्तन प्रदर्शित किया गया है। तालिका में ऋण एवं अग्रिम, यह स्पष्ट होता है कि प्रति वर्ष ऋण एवं अग्रिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रत्येक वर्ष ऋण एवं अग्रिम की राशि में वृद्धि देखी गई है, जिससे वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण एवं अग्रिम में लगातार वृद्धि की पुष्टि होती है। वर्ष 2015-2016 में यह राशि 254651.14 लाख थी, जो वर्ष 2024-2025 में 999439.64 लाख तक पहुँच गई है, अर्थात लगभग चार गुना ऋण में वृद्धि हुई है। प्रतिशत परिवर्तन के दृष्टिकोण से, वर्ष 2018-2019 के पश्चात् वृद्धि दर में तीव्रता देखी गई है। जैसे- 2019-2020 में 15.23% और तत्पश्चात 2020-2021 में 26.796%, 2023-

2024 में 25.208% तथा 2024-2025 में 24.406% की वृद्धि हुई। आरम्भिक वर्षों, 2015-2019 में वृद्धि दर 3% से लेकर 7.47% तक सीमित रही। जबकि बाद के वर्षों में (2019 के पश्चात) यह वृद्धि दर काफी तेजी से 15% से अधिक रही। उच्च प्रतिशत वृद्धि, आर्थिक विकास की आवश्यकताओं में वृद्धि अथवा बैंकिंग क्षेत्र की सक्रियता का संकेत देती है।

तालिका में ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ सकल एनपीए के आँकड़े और सकल एनपीए प्रतिशत को भी दर्शाया गया है। सकल एनपीए प्रतिशत किसी भी बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय स्वास्थ्य का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। यहाँ आँकड़े बैंक के प्रदर्शन, ऋण वितरण की गुणवत्ता और वित्तीय लचीलापन को परखने में सहायक हैं। सकल एनपीए वर्ष 2015-2016 में 22256.05 लाख ₹ था, जो कुल अग्रिम का 8.74% था। 2017-18 में यह बढ़कर 44758.33 लाख ₹ हो गया, जो कुल ऋण एवं अग्रिम का 15.79% प्रतिशत तक पहुँच गया था। यह सकल एनपीए की सबसे उच्च स्थिति थी, अर्थात उस वर्ष बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति खराब थी। उन वर्षों के बाद, बैंक के सकल एनपीए में धीरे-धीरे कमी आई, एवं 2020-21 में 13806.45 लाख ₹, जो कुल ऋण एवं अग्रिम का 3.1% था और 2024-2025 में 21440.43 लाख ₹, जो कुल ऋण का 2.15% रह गया। वर्ष 2017-18 में एनपीए दर सबसे अधिक 15.79 प्रतिशत थी, परंतु इसके बाद इसमें लगातार गिरावट देखी गई। आखिरी वर्ष 2024-2025 में एनपीए दर के प्रतिशत में काफ़ी कमी आई, जो 2.15% है, यह दर बैंकिंग क्षेत्र की सुधार की स्थिति के साथ एनपीए दर में लगातार गिरावट को दर्शाती है, जिससे संकेत मिलता है कि बैंकिंग क्षेत्र ने अपनी ऋण वसूली में सुधार किया है या डूबत ऋण की समस्या कम हुई है। 2018-2019 के बाद सुधार की प्रवृत्ति काफ़ी स्पष्ट है।

तालिका में ऋण और अग्रिम के साथ-साथ शुद्ध एनपीए के आंकड़े और प्रतिशत को भी प्रस्तुत किया गया है, जिसका उद्देश्य बैंक की वित्तीय स्थिति और ऋण वसूली की गुणवत्ता का मूल्यांकन करना है। 2015-16 में, शुद्ध एनपीए ₹20028.07 लाख था, जो कुल ऋण का 7.86% था। 2017-18 में, यह प्रतिशत उच्चतम स्तर पर, 8.95% पर पहुंच गया, जिसकी राशि ₹25359.15 लाख थी। 2018-19 से, बैंक में शुद्ध एनपीए में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जो 2018-19 में 6.48% थी, 2019-20 में घटकर 2.06% रह गई और 2020-21 में केवल 0.83% दर्ज की गई। वर्ष 2021-22 से लेकर वर्तमान वर्ष 2024-25 तक, यह शुद्ध एनपीए 0% है। इस अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक वर्षों में बैंक में डिफ़ॉल्ट की संख्या अधिक थी, किंतु समय के साथ संस्था की ऋण गुणवत्ता में सुधार हुआ। हाल के वर्षों में डिफ़ॉल्ट ऋण एवं एनपीए की स्थिति शून्य हो गई है, जिससे संस्था की वित्तीय स्थिति में सुदृढ़ीकरण का संकेत मिलता है। यह प्रवृत्ति इंगित करती है कि संस्था ने अपने ऋण वसूली प्रबंधन में सुधार किया है, जिसके परिणामस्वरूप डिफ़ॉल्ट ऋण की समस्या में उल्लेखनीय कमी आई है।

तालिका 6.2 - छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा सकल एनपीए के बीच सहसंबंध का अध्ययन।

	ऋण एवं अग्रिम	सकल एन पी ए		
वर्ष	X	Y	$x - \bar{x}$	$y - \bar{y}$
2015-2016	254651.14	22256.05	-232246.29	-1528.7
2016-2017	264325.25	30537.93	-222572.18	6753.21
2017-2018	283498.33	44758.33	-203399.1	20973.6
2018-2019	304684.62	41591.75	-182212.81	17807
2019-2020	351094.83	19450.96	-135802.6	-4333.8
2020-2021	445173.81	13806.45	-41723.619	-9978.3
2021-2022	521111.28	13366.34	34213.851	-10418
2022-2023	641627.69	14564.79	154730.26	-9219.9
2023-2024	803367.7	16074.21	316470.27	-7710.5
2024-2025	999439.64	21440.43	512542.21	-2344.3
कुल योग	**4868974.29**	**237847.24**		
माध्य	**486897.429**	**23784.724**		

$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$	$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$
53938338754.27	2336844.198	355028863.59
49538374864.81	45605791.28	-1503075774.66
41371193474.01	439892148.6	-4266012563.18
33201507763.67	317090175	-3244668227.40
18442345895.15	18781510.41	588536414.65
1740860382.46	99565952.02	416329702.65
1170587600.25	108542725.2	-356453037.84
23941453669.13	85007182.96	-1426602794.22
100153432426.81	59452026.14	-2440148455.13
262699518056.77	5495714.358	-1201549629.99
586197612887.33	**1181770070**	**-13078615501.52**

पियर्सन सहसंबंध (r) =

$$\frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x-x)^2\sum(y-\bar{y})^2}}$$

$$r = \frac{-13078615501.52}{\sqrt{586197612887.33 * 1181770070}}$$

$$r = \frac{-13078615501.52}{26320159461.9701}$$

$$r = -0.4969$$

सहसंबंध गुणांक का मान –1 से +1 तक होता है।

1= “+1” “पूर्ण धनात्मक संबंध”

2= “–1” “पूर्ण ऋणात्मक संबंध”

3= “0” “कोई संबंध नहीं”

तालिका और आँकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया कि ऋण एवं अग्रिम और सकल एनपीए के बीच सहसंबंध गुणांक –0.4969 है। यह मान मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि जैसे-जैसे बैंक के ऋण एवं अग्रिम बढ़े हैं, सकल एनपीए में कमी होते दिखाई दे रही है। शुरुआती वर्षों में एनपीए अधिक रहे, लेकिन समय के साथ बैंकिंग प्रणाली व्यवस्था में सुधार और अच्छे ऋण प्रबंधन के कारण एनपीए में कमी आई है। ऋणों और अग्रिमों में निरंतर वृद्धि बैंक व्यवसाय के विस्तार को दर्शाती है। लेकिन इसके बावजूद यदि एनपीए कम हो रहा है तो यह बैंक की ऋण गुणवत्ता, निगरानी और प्रभावी वसूली प्रणाली की अच्छी स्तिथि का संकेत है।

तालिका 6.3 - छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा शुद्ध एनपीए के बीच सहसंबंध का अध्ययन।

	ऋण एवं अग्रिम	**शुद्ध एन पी ए**		
वर्ष	**x**	**y**	$\mathbf{x - \bar{x}}$	$\mathbf{y - \bar{y}}$
2015-2016	254651.14	20028.07	-232246	10443.909
2016-2017	264325.25	19792.83	-222572	10208.669
2017-2018	283498.33	25359.15	-203399	15774.989
2018-2019	304684.62	19750.41	-182213	10166.249
2019-2020	351094.83	7231.43	-135803	-2352.731
2020-2021	445173.81	3679.72	-41723.6	-5904.441
2021-2022	521111.28	0	34213.85	-9584.161
2022-2023	641627.69	0	154730.3	-9584.161
2023-2024	803367.7	0	316470.3	-9584.161
2024-2025	999439.64	0	512542.2	-9584.161
कुल	**4868974.29**	**95841.61**		
माध्य	**486897.429**	**9584.161**		

$\mathbf{(x - \bar{x})^2}$	$\mathbf{(y - \bar{y})^2}$	$\mathbf{(x - \bar{x})(y - \bar{y})}$
53938338754	109075235.2	-2425559108
49538374865	104216922.8	-2272165704

41371193474	248850278	-3208618549
33201507764	103352618.7	-1852420787
18442345895	5535343.158	319506984.5
1740860382	34862423.52	246354646.7
1170587600	91856142.07	-327911056.4
23941453669	91856142.07	-1482959733
100153432426.81	91856142.07	-3033102029
262699518056.77	91856142.07	-4912287070
586197612887.33	**973317389.61**	**-18949162405.21**

$$\text{पियर्सन सहसंबंध (r)} = \frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{\sum(x-x)^2\sum(y-\bar{y})^2}}$$

$$r = \frac{-18949162405.21}{\sqrt{586197612887.33*973317389.61}}$$

$$r = \frac{-18949162405.21}{23886320988.60}$$

$$r = -0.7933$$

ऋण एवं अग्रिम और शुद्ध एनपीए के बीच सहसंबंध गुणांक r = – 0.7933 प्राप्त हुआ है, जो कि एक मज़बूत ऋणात्मक सहसंबंध) को दर्शाता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि जैसे-जैसे बैंक के ऋण एवं अग्रिम की राशि बढ़ती गई, वैसे-वैसे शुद्ध एनपीए में उल्लेखनीय कमी आई। यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से संकेत करती है कि बैंक की ऋण प्रबंधन नीतियाँ और वसूली समय के साथ प्रभावी हुए हैं।

परिकल्पना परीक्षण :

H_{01} - छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा सकल एनपीए के मध्य कोई सार्थक संबंध नहीं है।

H_{a1} - छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा सकल एनपीए के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध है।

उपयुक्त परिकल्पना में बैंक के ऋण एवं अग्रिम और सकल एन पी ए के सम्बन्ध की सार्थकता का अध्ययन किया गया है। प्राप्त आकड़ो का मध्यमान, प्रमाप विचलन, स्वतंत्र अंश(df), और परिकल्पना परीक्षण "टी परिकल्पना परीक्षण विधि" द्वारा 5% की सार्थकता स्तर पर किया गया है इसका विवरण तालिका में प्रदर्शित है।

क्रमांक	तुलनात्मक समूह	कुल रकम	माध्य (M)	प्रमाप विचलन (SD)	स्वतंत्रता अंश (df)	टी मूल्य (t)
1	**ऋण एवं अग्रिम**	4868974.29	486897.43	255211.81	9	5.6090
2	**सकल एन पी ए**	237847.24	23784.72	11458.961		

df = 9 के लिए 5 % सार्थकता पर टी सारणी मान (t) =2.262

टी मूल्य (t) > टी सारणी मान (t) = अंतर सार्थक है।

टी मूल्य (t) < टी सारणी मान (t) = अंतर सार्थक नहीं है।

तालिका के अनुसार -

टी मूल्य (t) 5.6090 > 2.262 टी सारणी मान (t) = अंतर सार्थक है।

उपयुक्त तालिका द्वारा दर्शाया गया है कि "टी का मूल्य मान" "टी के सारणी मान" से अधिक है जो दर्शाता है कि शून्य परिकल्पना (H01) को अस्वीकार किया जाता है और वैकल्पिक परिकल्पना (Ha1) को स्वीकार किया जाता है जिससे ज्ञात होता है की बैंक के कुल ऋण एवं अग्रिम और सकल एनपीए में महत्वपूर्ण संबंध है।

H_{02}- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा शुद्ध एनपीए के मध्य कोई संबंध नहीं है।

H_{a2}- छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के ऋणों और अग्रिमों तथा शुद्ध एनपीए के मध्य महत्त्वपूर्ण संबंध है।

उपयुक्त परिकल्पना में बैंक के ऋण एवं अग्रिम और शुद्ध एन पी ए के सम्बन्ध की सार्थकता का अध्ययन किया गया है। प्राप्त आकड़ो का मध्यमान, प्रमाप विचलन, स्वतंत्र अंश(df), और परिकल्पना परीक्षण "टी परिकल्पना परीक्षण विधि" द्वारा 5% की सार्थकता स्तर पर किया गया है इसका विवरण तालिका में प्रदर्शित है।

क्रमांक	तुलनात्मक समूह	कुल रकम	माध्य (M)	प्रमाप विचलन (SD)	स्वतंत्रता अंश (df)	टी मूल्य (t)
1	**ऋण एवं अग्रिम**	4868974.29	486897.43	255211.81	9	5.7274
2	**शुद्ध एन पी ए**	95841.61	9584.16	10399.35		

df = 9 के लिए 5 % सार्थकता पर टी सारणी मान (t) =2.262

टी मूल्य (t) > टी सारणी मान (t) = अंतर सार्थक है।

टी मूल्य (t) < टी सारणी मान (t) = अंतर सार्थक नहीं है।

तालिका के अनुसार -

टी मूल्य (t) 5.7274 > 2.262 टी सारणी मान (t) = अंतर सार्थक है।

उपयुक्त तालिका द्वारा दर्शाया गया है कि "टी का मूल्य मान" "टी के सारणी मान" से अधिक है जो दर्शाता है कि शून्य परिकल्पना (H01) को अस्वीकार

किया जाता है और वैकल्पिक परिकल्पना (Ha1) को स्वीकार किया जाता है जिससे ज्ञात होता है की बैंक के कुल ऋण एवं अग्रिम और शुद्ध एनपीए में महत्वपूर्ण संबंध है।

निष्कर्ष:

ऋण एवं अग्रिम: ऋण एवं अग्रिम में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2015-16 में यह राशि ₹2,54,651.14 करोड़ थी, जो वर्ष 2024-25 में बढ़कर ₹9,99,439.64 करोड़ हो गई। इससे स्पष्ट होता है, कि बैंक का ऋण वितरण लगातार बढ़ा है और बैंक की ऋण वृद्धि अत्यंत मजबूत रही है।

सकल एनपीए : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सकल एनपीए का स्तर 8.74% दर्ज किया गया था, जो 2024-25 में घटकर मात्र 2.15% रह गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2017-18 के दौरान सकल एनपीए में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और यह 15.78% के उच्चतम स्तर तक पहुँच गया। तथापि, 2018-19 से इसमें निरंतर गिरावट का देखने को मिला हैं। यह संकेत है, कि बैंक ने एनपीए प्रबंधन और ऋण गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया हैं।

शुद्ध एनपीए : वित्तीय वर्ष 2015-16 में बैंक का शुद्ध एनपीए 7.86% था।वित्तीय वर्ष 2019-20 में यह घटकर 2.06% रह गया तथा 2021-22 से यह पूर्णतः शून्य (0%) हो गया। यह दर्शाता है, कि बैंक ने अपने सभी एन पी ए के ऋणों पर पूर्ण प्रावधान कर लिया है, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध हानि की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो गई है।

ऋण एवं अग्रिम और सकल एनपीए के बीच सम्बन्ध : "ऋण एवं अग्रिम और सकल एनपीए के बीच मध्यम नकारात्मक सहसंबंध है। ऋण जितना बढ़ा, एनपीए उतना घटा — यह बैंक की संपत्ति गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है।"

ऋण एवं अग्रिम और शुद्ध एनपीए के बीच संबंध : यह दर्शाता है कि ऋण एवं अग्रिम और शुद्ध एनपीए के बीच एक मजबूत ऋणात्मक सहसंबंध है। इसका अर्थ है कि जैसे-जैसे बैंक के ऋण एवं अग्रिम बढ़े हैं, वैसे-वैसे शुद्ध एनपीए लगातार घटे हैं और अंततः शून्य (0) हो गए हैं। यह स्थिति बैंक की बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता तथा एनपीए प्रबंधन में सुधार को दर्शाती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. सी.एच. श्रीनिवास, अकुला श्रीनिवास, (2018) "परफॉर्मेंस ऑफ तेलंगाना ग्रामीण बैंक इन तेलंगाना" एशियन जर्नल ऑफ मल्टी-डिसिप्लिनरी रिसर्च, 4(2)
2. सुनीत सुरेश चंद्र कोपरा, (2017), "नॉन परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स ऑफ महाराष्ट्र: ए कंपैरेटिव एनालिसिस" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड कंप्यूटिंग, खंड 7, अंक संख्या 1,
3. डॉ. सोनिया नरूला और मोनिका सिंगला (2014), "अंपयारिकल स्टडी ऑन परफॉर्मिंग असेट्स ऑफ बैंक" इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड रिसर्च इन कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज, वॉल्यूम 2, इश्यू 1, जनवरी 2014
4. बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 से 2024-25 तक।